के. मनोरमा

बनाम

भारत गणराज्य का संघ प्रतिनिधि द्वारा जनरल मैनेजर

दक्षिण रेलवे और अन्य

(सिविल अपील की संख्या 2379/2005)

सितंबर 29, 2010

(आर. वी. रवींद्रन और एच. एल. गोखले, जे. जे.),

सेवा कानूनः

पदोन्नति में आरक्षण-दो पद-चयन - अपीलार्थी द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई कि पहले नियुक्त व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया गया था, न कि इसलिए कि वह एक अनुसूचित जाति और इसलिए अपीलार्थी को अनुसूचित जाति के रूप में उसकी स्थिति के आधार पर पदोन्नत किया जाना चाहिए था। दूसरे नियुक्त व्यक्ति के स्थान पर जाति उम्मीदवार-माना गयाः पहली नियुक्ति अनुसूचित जाति से थी और थी अन्य उम्मीदवारों को अलग रखते हुए उन्हें जो रिक्ति आवंटित की गई थी- वास्तव में, पहले नियुक्त व्यक्ति को, दूसरे नियुक्त व्यक्ति से कम अंक मिले और उसका चयन मूल रूप से इसलिए हुआ क्योंकि वह अनुसूचित जाति का उम्मीदवार था- अन्यथा भी, सिद्धांत यह है कि जब अनुसूचित जाति से

संबंधित सदस्य अपनी योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता के मैदान में चुना जाता है, उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटे में नहीं गिना जाएगा, बल्कि उसे खुले उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा, यह केवल खुली प्रतियोगिता द्वारा भर्ती के संबंध में लागू होगा, न कि वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर होने वाली पदोन्नति के लिए।

पदोन्नति में आरक्षण-जब एक पद संवर्ग बहु-पद संवर्ग बन जाता है, और परिणामस्वरूप दो सीटे उपलब्ध होने पर, दो सीटों में से एक को आरक्षित सीट के रूप में माना जाना चाहिए।

अपीलार्थी अनुसूचित जाति से संबंधित दक्षिण रेलवे में मुख्य विधि सहायक के रूप में कार्यरत था। उस पद से ऊँचा पद सहायक विधि अधिकारी का था। प्रारंभ में 'सहायक विधि अधिकारी एकल पद संवर्ग था। यह एक खुली श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भरा गया था वर्ष 1991 में। इसके बाद दो पदों का सृजन किया गया। पदों को वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर भरा जाना था। एक अधिसूचना 10.11.1994 को जारी जिसमें 10 वरिष्ठतम योग्य उम्मीदवार दोनों पदों के लिए पात्र माने गए। उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। आठ विधि सहायकों ने योग्यता अंक प्राप्त किए और साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए पात्र पाए गए। संबंधित समिति उन दो पदों के लिए प्रतिवादी सं..3 और 4 की सिफारिश की। उनमें से, प्रत्यर्थी नं. 3 एक

अनुसूचित जाति का उम्मीदवार था। उन दोनों के लिए पदोन्नति आदेश 26.5.1995 पर जारी किया गया था।

अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सं. 4 की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी कि प्रत्यथी नं 3 को उसकी योग्यता के आधार पर सहायक विधि अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई थी और इसलिए नहीं कि वह एक अनुसूचित जाति का था और, इसलिए, अपीलार्थी को अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में उसकी स्थिति के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 4 के स्थान पर पदोन्नत किया जाना चाहिए था।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने ओ.ए. को अनुमति दी और घोषणा की कि प्रत्यर्थी नं 3 का चयन अपनी योग्यता के आधार पर एक अनारक्षित रिक्ति में था। प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 को निर्देशित किया प्रत्यर्थी सं. 4 के चयन में अंकों और वरिष्ठता के अनुसार बनाया गया और उसके ऊपर या तो अंकों पर या वरिष्ठता मे कोई अनुसूचित जाति का उम्मीदवार नहीं था। प्रत्यर्थी सं. 4 का चयन गलत माना गया। हालाँकि, चूंकि वे इस बीच में सेवानिवृत्त हो गए थे, इसलिए प्राप्त परिलब्धियाँ को परिवर्तित न करने का निर्देश दिया गया था। न्यायाधिकरण ने आगे निर्देश दिया कि यदि अपीलार्थी उपयुक्त पाया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 3 के चयन की तारीख से सेवा में वरिष्ठता का हकदार माना जाएगा। यद्यपि वह जिस तारीख को

उसने उच्च पद का प्रभार वास्तव में ग्रहण किया था, उस तारीख तक उसे वेतन नहीं मिलेगा।

प्रत्यर्थी सं 1 और 2 ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएँ दायर की जिन्हें अनुमति दी गई थी। हस्तगत अपील उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।

न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया गया:-

1. दो रिक्तियों में से एक जो वर्ष 1994 में हुई को आरक्षित माना जाना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रोस्टर में अन्यथा आरक्षित उम्मीदवार के लिए पहला अंक अभिप्रेत था। चूंकि, 1991 में, यह एक एकल संवर्ग था, इसलिए इसे इस रूप में माना जाता था। जब एक पोस्ट कैडर बहु-पोस्ट कैडर बन गया, और परिणामस्वरूप 1994 में दो सीटें उपलब्ध हो गईं, तो विभाग को दो सीटों में से एक को आरक्षित सीट के रूप में मानना पड़ा। (पैरा 11) (849-एच,) (850-ए-बी)

2. उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का चार्ट दर्शाया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 4 ने उच्चतम अंक प्राप्त किए थे अर्थात। 128. दो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार क्रमशः 127 और 125 अंकों के साथ उनके बगल में थे। इसके बाद, प्रत्यर्थी सं. 3 और दो अन्य उम्मीदवार ने 124 अंक प्राप्त किए। प्रत्यर्थी संख्या 3 को उनमें से चुना गया था, अनिवार्य रूप से क्योंकि यह एक अनुसूचित जाति की रिक्ति थी, जो अन्य उम्मीदवारों को अलग रखते

हुए उसे आवंटित की गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें नंबर एक और प्रतिवादी नंबर 4 (उच्च अंक वाले) को दूसरे नंबर पर रखा गया। ट्रिब्यूनल ने माना था कि यदि प्रत्यर्थी स. 3 को प्रत्यर्थी सं. 4 से कम अंक मिले तभी उसे अनुसूचित जाति बिंदु के विरुद्ध चयनित माना जा सकता है। न्यायाधिकरण ने यह एहसास नहीं किया कि प्रत्यर्थी संख्या 3 को, वास्तव में, प्रत्यर्थी संख्या 4 से कम अंक मिले थे और उसका चयन मूल रूप से इसलिए हुआ क्योंकि वह अनुसूचित जाति का उम्मीदवार था। अन्यथा भी, सिद्धांत यह है कि जब कोई अनुसूचित जाति का सदस्य संबंधित होता हैं अपनी योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता क्षेत्र में चयनित होता है, उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटे में नहीं गिना जाएगा, बल्कि खुले उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा, केवल खुली भर्ती के संबंध में लागू किया जाएगा, न कि प्रतिस्पर्धा वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति में। "(पैरा 14) (854-जी-एच, 855-ए-डी)

3. अपीलकर्ता ने अधीनस्थ कर्मचारियों की पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले नियमों पर भरोसा किया था और उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि जिन उम्मीदवारों ने 80 प्रतिशत अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें शीर्ष पर रखा जाना चाहिए, यह दर्शाता है कि उन्हें समुदाय की परवाह किए बिना चुना जाना कारक है। हालाँकि, किसी भी उम्मीदवार ने 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए थे, और इसलिए, उस स्तर पर पात्र होने के लिए उत्कृष्ट नहीं माना जा सकता था। उस

हिसाब से भी प्रत्यर्थी संख्या 3 के चयन को सामुदायिक कारक के बावजूद केवल योग्यता के आधार पर नहीं माना जा सकता है। (पैरा 15) (855-ई; 856-बी)

आर. के. सभरवाल और अन्य। वी. पंजाब राज्य और अन्य। 1995 (2) एस.सी.सी. 745 लागू नहीं होता

अजीत सिंह जानुजा और अन्य। वी. पंजाब राज्य और अन्य। 1996 (2) एस.सी.सी. 715-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भः

1995 (2) एस.सी.सी. 745	अप्रयोज्य माना गया	पैरा 4,5,14
1996 (2) एस.सी.सी. 715	संदर्भित	पैरा 5

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं 2379/2005 ।

मद्रास उच्च न्यायालय, के रिट याचिका संख्या 1311/1999 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांकित 28.01.2003 से ।

सी. के. चंदरसेकर, एस. आर. सेतिया अपीलार्थी की ओर से।

ए. के. गांगुली, वी. मोहन, श्वेता, ए. के. शर्मा, श्रीकांत एन. तेरडाल, वी. बालचंद्रन, वी. रामसुब्रमण्यन, ए. लक्ष्मी नारायणन । प्रत्यर्थीगण की ओर से

न्यायालय का निर्णय न्यायधीश गोखले, जे. द्वारा दिया गया था :-

1. यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 28.1.2003 के फैसले और आदेश को चुनौती देने का प्रयास करती है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा दायर 1999 की रिट याचिका संख्या 1311 की अनुमति दी गई है, और पारित आदेश को रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण दिनांक 27.11.1998 जिसने अपीलकर्ता द्वारा दायर 1996 के मूल आवेदन संख्या 891 को अनुमति दी थी। ओ.ए. इस प्रकार अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दी गई।

2. इस अपील से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः - नवंबर 1994 में प्रासंगिक समय पर, अपीलकर्ता मुख्य कानून सहायक के रूप में काम कर रहा था जो दक्षिणी रेलवे में समूह-'सी; पद था। इस पद से ऊपर का पद सहायक विधि अधिकारी का है जो ग्रुप-'बी' पद है। प्रासंगिक समय में दक्षिणी रेलवे में सहायक विधि अधिकारियों की कुल कैडर शक्ति तीन थी। प्रारंभ में जब 'सहायक विधि अधिकारी एकल पद कैडर था, वर्ष 1991 में, इसे एक खुली श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भरा गया था। इसके बाद वर्ष 1994 में जब दो और पद सृजित किये गये तो आरक्षण लागू हुआ। पद वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरे जाने थे। एक अधिसूचना 10.11.1994 को जारी की गई थी, जिसमें 10 वरिष्ठतम उम्मीदवारों को दो पदों के लिए विचार किए जाने के लिए पात्रता में शामिल किया गया है। (यहां दूसरा प्रत्यर्थी दक्षिणी रेलवे का मुख्य व्यक्तिगत अधिकारी है)। उनकी

उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई। आठ कानून सहायकों ने अर्हता प्राप्त अंक प्राप्त किए और साक्षात्कार के लिए बी बुलाए जाने के पात्र बन गए (उनमें से एक ने बाहर निकलने का विकल्प चुना)। संबंधित समिति ने उन दो पदों के लिए प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 की सिफारिश की। उनमें से, प्रत्यर्थी संख्या 3 अनुसूचित जाति का उम्मीदवार है। तदनुसार, उन दोनों का पदोन्नति आदेश 26.5.1995 को जारी किया गया था।

3. अपीलार्थी भी अनुसूचित जाति से संबंधित है और इसका विचार था कि प्रत्यर्थी संख्या 3 (श्री एम. सिद्दिया), उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर सहायक विधि अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था, न कि इसलिए कि वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवार थे। यह उनका तर्क था कि प्रत्यर्थी संख्या 4 (श्री के.राजगोपालन नायर) खुली श्रेणी से संबंधित हैं, उन्हें चाहिए अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में उनकी स्थिति के आधार पर सहायक विधि अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है। इसलिए, वह रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष 14.2.1996 को प्रतिवेदन किया गया, पर लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में उपरोक्त निर्दिष्ट ओ. ए. दायर किया। (इसके बाद चेन्नई में न्यायाधिकरण के रूप में संदर्भित)। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने अपने जवाब कथन दाखिल किया कि रेल्वे बोर्ड के निर्णय दिनांकित 29.7.1993 अनुसार 4 से कम वाले छोटे संवर्गों में पदों के लिए, जब कैडर

में कोई एससी/एसटी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था, 40 अंकों की सूची के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाना था। मॉडल 40 प्वाइंट रोस्टर के अनुसार पहला अंक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को भरना होगा और अगले दो अंकों को अनारक्षित माना जाना था। उनके उत्तर के पैरा 1 और 2 में प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 निम्नानुसार कहा गया है:-

> "इस चयन में, दो रिक्तियों के लिए भरे जाने वाले रोस्टर बिंदु संख्या 2 और 3 थे। दोनों बिंदु यूआर (यानी अन-आरक्षित) अंक हैं। पहला बिंदु जो एससी बिंदु था, उसे एक यूआर उम्मीदवार भर दिया गया था, एक रिक्ति की अधिसूचना जारी होने से, दो रिक्तियों में से, एक पद को एससी माना गया।"

4. अपीलकर्ता ने सी.ए.टी. के समक्ष प्रस्तुत किया कि यदि कोई अनुसूचित जाति का उम्मीदवार किसी गैर-आरक्षित पद के लिए प्रतिस्पर्धा करता है और चयनित हो जाता है, तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटा में नहीं गिना जाना चाहिए। अपीलकर्ता के अनुसार, यदि योग्य उम्मीदवारों में सबसे वरिष्ठ अनुसूचित जाति से है, तो पदोन्नत होने पर उसे एक खुली श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में माना जाना चाहिए और उसे अनुसूचित जाति के कोटे में नहीं गिना जाना चाहिए। इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय आर.के. सभरवाल और अन्य बनाम पंजाब

राज्य और अन्य, (1995 (2) एससीसी 745) के समर्थन पर भरोसा किया गया था।

5. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने इस श्सबमिशनश् को स्वीकार कर लिया और नोट किया कि आर.के. में पूर्वसर्ग। सभरवाल और अन्य। (सुप्रा) को अजीत सिंह जनुजा और अन्य के पैरा 11 में दोहराया गया था। बनाम पंजाब राज्य और अन्य। (1996 (2) एससीसी 715) जिसमें आर.के. में फैसले का जिक्र करने के बाद। सभरवाल (सुप्रा) की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि यदि एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को उसकी योग्यता के आधार पर नियुक्त/पदोन्नत किया गया है, तो ऐसे उम्मीदवार को उनके लिए निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत में नहीं गिना जाएगा जैसा कि आर.के. सभरवाल का मामला में कहा गया है।

6. ट्रिब्यूनल ने इसलिए, आदेश दिनांक 27.11.1998 द्वारा ओ.ए. की अनुमति दी। घोषणा की कि प्रत्यर्थी सं. 3 का चयन उसकी अपनी योग्यता के आधार पर एक अनारक्षित रिक्ति में किया गया था। इसने प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को अपीलकर्ता को आरक्षित श्रेणी में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, बशर्ते कि वह किए गए चयन में अंकों और वरिष्ठता के अनुसार योग्य हो, और यदि अंकों या वरिष्ठता में उससे ऊपर कोई एससी उम्मीदवार नहीं था। प्रत्यर्थी संख्या 4 का चयन गलत माना गया। हालाँकि, चूँकि वे इस बीच सेवानिवृत्त हो गए थे, इसलिए प्राप्त परिलब्धियों

में गड़बड़ी न करने का निर्देश दिया गया था। ट्रिब्यूनल ने आगे निर्देश दिया कि यदि अपीलकर्ता फिट पाया गया तो प्रत्यर्थी संख्या 3 के चयन की तारीख से सेवा में वरिष्ठता का हकदार माना जाएगा, हालांकि उसे वास्तव में उच्च पद का कार्यभार संभालने की तारीख तक वेतन नहीं मिलेगा।

7. इस निर्णय और आदेश से व्यथित होना प्रत्यर्थी नं. 1 और 2 ने मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 1311 की 1999 दायर की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया। इससे दुखी होकर, अपीलार्थी ने वर्तमान अपील दायर की है।

8. जैसा कि पहले कहा गया था, अपीलकर्ता के तर्क का मुख्य आधार यह था कि चूंकि प्रत्यर्थी नंबर 3 का चयन योग्यता के आधार पर किया गया था, इसलिए उसे अनुसूचित जाति की सीट पर नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए अनुसूचित जाति की रिक्ति अगले अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को दी जानी चाहिए। योग्यता क्रम, और अपीलकर्ता अगला उम्मीदवार था। इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 4 (श्री के. राजगोपालन नायर) को खुली श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में पदोन्नत नहीं किया जाना चाहिए था और वह पद अपीलकर्ता को आवंटित किया जाना चाहिए था। अपीलकर्ता ने रेलवे बोर्ड के आदेश दिनांक 29.7.1993 पर भरोसा किया। जो इस संबंध

में, हैदराबाद में ट्रिब्यूनल के पूर्ण-पीठ के फैसले को लागू करने के लिए जारी किया गया था, जिसमें कहा गया है कि जहां एसटी/एससी उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया गया था, उनकी वरिष्ठता को आरक्षित उम्मीदवारों के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 29.7.1993 का प्रासंगिक भाग पैरा (VI) में निम्नानुसार स्पष्ट है -

> "(VI) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किया गया है, उसे उपलब्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की गिनती के लिए आरक्षित उम्मीदवार माना जाना चाहिए-
>
> केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण/हैदराबाद की पूर्ण पीठ के फैसले के अनुसार, जिन एससी/एसटी उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किया गया है, उन्हें आरक्षित उम्मीदवारों के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए। बोर्ड के दिनांक 16.06.1992 के पत्र में यह भी कहा गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को आरक्षित कोटा से अधिक होने पर भी पैनल/चयन सूची में रखा जा सकता है, यदि ऐसे

उम्मीदवार योग्यता/वरिष्ठता के आधार पर सामान्य पदों के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। आरक्षित कोटा की गणना करते समय उपलब्ध एससी/एसटी उम्मीदवारों की गिनती के उद्देश्य से इन एससी/एसटी उम्मीदवारों को बाहर रखा जाना चाहिए।"

9. अब, जहाँ तक इस पहलू का संबंध है, प्रत्यर्थी नं. 1 और 2 ने यह स्पष्ट कर दिया था कि कहाँ पद 4 से कम थे में, 40 अंकों का रोस्टर लागू होने की उम्मीद थी। रोस्टर के अनुसार उस सूची में पहला अंक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार लिए था और दूसरे और तीसरे अंक अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए थे। यह मॉडल सूची के नीचे एक टिप्पणी है जो इस प्रकार हैः -

"नोट-यदि किसी विशेष वर्ष में केवल दो रिक्तियां भरी जानी हैं, तो एक से अधिक रिक्तियों को आरक्षित के रूप में नहीं माना जा सकता है और यदि केवल एक रिक्ति है, तो इसे अनारक्षित माना जाना चाहिए। यदि इस कारण पर, एक आरक्षित अंक को अनारक्षित माना जाता है, आरक्षण बाद की तीन भर्तियों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता हैं।"

10. यह प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की ओर से यह निवेदन किया गया था कि इस नोट को देखते हुए 1991 वर्ष में पहली रिक्ति अनारक्षित माना

गया है, जब दो रिक्तियां बाद में हुई, उनमें से एक को आरक्षित माना गया। यह उपरोक्त नोट के अनुसार था, जिसमें कहा गया था कि जहां आरक्षित बिंदु को अनारक्षित माना जाता है, आरक्षण को आगे बढ़ाया जाना है। प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 इसलिए, दो रिक्तियों में से एक को आरक्षित माना गया।

11. हमारे विचार में, प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के निवेदन को अच्छी तरह से लिया गया है। उन्हें दोनों में से एक रिक्तियां जो वर्ष 1994 में आरक्षित के रूप में हुईं, लिया गया हैं। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि रोस्टर में पहला अंक आरक्षित उम्मीदवार के लिए था। चूंकि, वर्ष 1991 में, यह एक एकल पद था। कैडर के बाद, इसे अनारक्षित माना गया था। जब एकल पद संवर्ग एक बहु-पद संवर्ग बन गया, और परिणामस्वरूप दो 1994 में सीटें उपलब्ध हुईं, उन्हें दो सीटों में से एक को आरक्षित सीट के रूप में मानना पड़ा। इसलिए अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में श्री सिद्धैया के चयन को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

12. अपीलकर्ता का निवेदन कि प्रत्यर्थी संख्या 3 का चयन उसकी योग्यता के आधार पर किया गया था और श्री के. राजगोपालन नायर को रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 14.4.1983 के विपरीत पैनल में रखा गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने ट्रिब्यूनल के समक्ष अपने अतिरिक्त उत्तर के

पैरा 10 में इस कथन का खंडन किया था। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश के पैरा 14 में इस प्रकार कहाः-

> "14. पैराग्राफ 10 में दिए गए संदर्भ का इस मामले में निर्णय के बिंदु पर कोई असर नहीं पड़ता है। यह भी है प्रत्यर्थियों की ओर से यह तर्क कि चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 3 अनुसूचित जाति कोटे में सबसे वरिष्ठ है, वह सूचीबद्ध है। सवाल यह है कि उसने उक्त चयन में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए है। इसलिए, उनके अनुसूचित जाति के उम्मीदवार होने का सवाल इस वजह से समाप्त हो जाता है कि वे चयन में मेधावी उम्मीदवार हैं। यदि प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम सामने आया है प्रत्यर्थी संख्या 3 से अधिक अंक और प्रत्यर्थी 3 के अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में वरिष्ठ होने का सवाल है, तो प्रत्यर्थी संख्या 3 को आरक्षित रिक्ति में सूचीबद्ध किया जाना उचित होगा। लेकिन यहां ऐसा मामला नहीं था।"

13. उत्तरदाता सं. 1 और 2 इंगित करते हैं कि यह निष्कर्ष तथ्यों पर गलत है। उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों का चार्ट हमारे सामने पेश किए गए हैं। चार्ट इस प्रकार है-

<u>सहायक कानून के पद के लिए चयन</u>

स्केल आरएस में कार्यालय। 2000-3500

विवा आवाज चालू 27.04.1995

रिक्तियों की संख्या 2 (अनुसूचित जाति-1: यूआर-1)

समिति के सदस्यः

1. एसडीजीएम

2. एफए और सीएओ

3. सीपीओ

4. सेल श्री आर. मोहन दास

क्र. सं.	नाम व पद	जन्म दिनांक	नियुक्ति दिनांक	दिनांक-पदोन्नति से वर्तमान ग्रेड	शैक्षणिक योग्यता
1	एम. सिद्दिया (sc) CLA\HQRS	04-08-43	16-06-65	09-05-85	B.Sc, B.L
कुल प्राप्तांक (200 अंक)				कुल	टिप्पणी

पेशेवर दक्षता	सेवा का रिकार्ड(25)	व्यक्तित्व पता एवं नेतृत्व/शैक्षणिक तकनीकी योग्यता (25)			
91	15	18		**124**	
क्र. सं.	नाम व पद	जन्म दिनांक	नियुक्ति दिनांक	दिनांक-पदोन्नति से वर्तमान ग्रेड	शैक्षणिक योग्यता
2	के. राजागोपालन नायर ASST. SEC. (ADHOC) RRT	24-08-39	16-11-63	01-04-87	B.Sc. LLB
कुल प्राप्तांक (200 अंक)				कुल	टिप्पणी
पेशेवर दक्षता	सेवा का रिकार्ड(25)	व्यक्तित्व पता एवं नेतृत्व/शैक्षणिक			

		तकनीकी योग्यता (25)			
91	21	16		**128**	
क्र. सं.	नाम व पद	जन्म दिनांक	नियुक्ति दिनांक	दिनांक-पदोन्नति से वर्तमान ग्रेड	शैक्षणिक योग्यता
3	वी. सुब्रहमण्यम L.O. (ADHOC) ICF	10-03-40	31-05-62	23-11-87	B.A, B.G.L. Diploma In Labour laws with Admin Law
कुल प्राप्तांक (200 अंक)				कुल	टिप्पणी

पेशेवर दक्षता	सेवा का रिकार्ड(25)	व्यक्तित्व पता एवं नेतृत्व/शैक्षणिक तकनीकी योग्यता (25)		
92	18	17	**127**	

क्र. सं.	नाम व पद	जन्म दिनांक	नियुक्ति दिनांक	दिनांक-पदोन्नति से वर्तमान ग्रेड	शैक्षणिक योग्यता
4	एम. अब्दुल खादिर CLA\DPO \MYS	01-11-43	11-09-43	01-04-90	B.A, LLB
कुल प्राप्तांक (200 अंक)				कुल	टिप्पणी
पेशेवर दक्षता	सेवा का रिकार्ड(25)	व्यक्तित्व पता एवं नेतृत्व/शैक्षणिक तकनीकी योग्यता (25)			
92	17	15		**124**	
क्र. सं.	नाम व पद	जन्म दिनांक	नियुक्ति दिनांक	दिनांक-पदोन्नति से वर्तमान ग्रेड	शैक्षणिक योग्यता
5	के. मनोरमा (sc)	22-12-60	13-11-81	24-07-90	B.A, B.L

	CLA\HQRS				
कुल प्राप्तांक (200 अंक)				कुल	टिप्पणी
पेशेवर दक्षता	सेवा का रिकार्ड(25)	व्यक्तित्व पता एवं नेतृत्व/शैक्षणिक तकनीकी योग्यता (25)			
91	15	16		**122**	
क्र. सं.	नाम व पद	जन्म दिनांक	नियुक्ति दिनांक	दिनांक-पदोन्नति से वर्तमान ग्रेड	शैक्षणिक योग्यता
6	आर. मुथुसैमी CLA\DPO\O\MAS	05-05-55	22-12-79	03-04-91	B.Sc.LLB
कुल प्राप्तांक (200 अंक)				कुल	टिप्पणी

पेशेवर दक्षता	सेवा का रिकार्ड(25)	व्यक्तित्व पता एवं नेतृत्व/शैक्षणिक तकनीकी योग्यता (25)			
91	16	17		**124**	
क्र. सं.	नाम व पद	जन्म दिनांक	नियुक्ति दिनांक	दिनांक-पदोन्नति से वर्तमान ग्रेड	शैक्षणिक योग्यता
7	टी.पी भास्कर सीएलए/एम एएस	26-08-55	31-07-91	24-07-91	एमए, एलएलबी
कुल प्राप्तांक (200 अंक)				कुल	टिप्पणी
पेशेवर दक्षता	सेवा का रिकार्ड(25)	व्यक्तित्व पता एवं नेतृत्व/शैक्षणिक तकनीकी योग्यता (25)			
95	15	15		**125**	

(आर. मोहनदास) (वी. नटराजन) (पी. मुरूगन)

14. जैसा कि इस चार्ट से देखा जा सकता है कि यह प्रत्यर्थी नं. 4 जिसने उच्चतम अंक प्राप्त किए थे अर्थात 128. श्री वी. सुब्रमण्यन और श्री टी. पी. भास्कर क्रमशः 127 और 125 अंकों के साथ उनके बाद हैं। इसके बाद, अन्य उम्मीदवार हैं जैसे श्री सिद्धैया, श्री अब्दुल खादर और श्री मुथुसामी जो सभी 124 अंक प्राप्त करते हैं। श्री सिद्धैया ने उनमें से चुना गया, अनिवार्य रूप से क्योंकि यह एक अनुसूचित जाति की रिक्ति थी जो उन्हें अन्य उम्मीदवार को अलग रखते हुए आवंटित की गई थी। इतना ही नहीं, उन्हें नंबर एक पर रखा गया और प्रत्यर्थी नंबर 4 (अधिक अंक वाले) को नम्बर दो पर रखा गया। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि यदि प्रत्यर्थी संख्या 3 को प्रत्यर्थी संख्या 4 से कम अंक मिलते हैं, तो ही अनुसूचित जाति बिंदु के विरुद्ध चुना जाना वह ऐसा कर सकता है। कहा जाए न्यायाधिकरण ने माना कि यदि प्रत्यर्थी संख्या 3 को प्रत्यर्थी संख्या 4 से कम अंक मिले, तभी उसे अनुसूचित जाति बिंदु के विरुद्ध चयनित माना जा सकता है। न्यायाधिकरण को यह एहसास नहीं हुआ कि तीसरे प्रत्यर्थी को वास्तव में चैथे प्रत्यर्थी से कम अंक मिले थे, और उसका चयन मूल रूप से इसलिए हुआ क्योंकि वह अनुसूचित जाति का उम्मीदवार था। इस स्थिति को देखते हुए, वर्तमान मामले में रेलवे बोर्ड के दिनांक 29.7.1993 के पत्र में निहित निर्देश का लागू करने का कोई अवसर नहीं और न ही आर.के. सभरवाल का निर्णय (सुप्रा) के प्रस्तावों को लागू करने का कोई अवसर है। अन्यथा भी, यह सिद्धांत कि जब अनुसूचित जाति का

कोई सदस्य अपनी योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता के क्षेत्र में चुना जाता है, तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटे में नहीं गिना जाएगा, बल्कि उसे खुले उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा। यह केवल खुली प्रतियोगिता द्वारा भर्ती के संबंध में लागू होगा, वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर होने वाली पदोन्नति पर नहीं।

15. अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि जिन उम्मीदवारों ने 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें शीर्ष पर रखा गया है जो दर्शाता है कि चाहे सामुदायिक कारक कुछ भी हो, उन्हें चुना जाना है। अपीलार्थी के निवेदन में श्री एम. सिद्धैया को ऐसे ही एक उम्मीदवार के रूप में माना जाना था। अब दो प्रासंगिक नियम 204.8 और 204.9 निम्नानुसार हैंः

> " 204.8 सफल उम्मीदवारों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा -
>
> निम्नलिखित हैः
>
> (1) 80 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों को श्रेणीबद्ध किया गया ' उत्कृष्ट '।
>
> (2) 60 प्रतिशत से 79 प्रतिशत के बीच अंक प्राप्त करने वाले 'अच्छा के रूप में वर्गीकृत किया गया।

204.9 पैनल में ऐसे कर्मचारी शामिल होने चाहिए जो चयन में अर्हता प्राप्त की थी, रिक्तियों की संख्या के अनुरूप जिसके लिए चयन आयोजित किया गया था। 'आउटस्टैंडिंग' श्रेणी हासिल करने वाले को शीर्ष पर रखा जाएगा और उसके बाद' '

के भीतर वरिष्ठता बनाए रखी जाएगी।"

यह ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसा कि पहले उल्लिखित अंकों से देखा गया है, कि किसी भी उम्मीदवार ने 80% से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं, और इसलिए, उस स्तर पर पात्र होने के लिए उत्कृष्ट नहीं माना जा सकता है। इस आधार पर भी श्री एम. सिद्दिया के चयन को सामुदायिक कारक के बावजूद केवल योग्यता के आधार पर नहीं माना जा सकता है।

16. इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय और आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए, यह अपील खारिज की जाती हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

डी. जी

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार टॉक, आर.जे.एस., द्वारा किया गया हैं।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता हैं। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।